



महाराजिन में दिखेगा...

■ वर्ष 29 अंक 32



www.swatantrammat.com

# स्वत्र मत



नीता अंबानी दोबारा...

डाक/नगर संस्करण

■ जबलपुर शुक्रवार 26 जुलाई 2024

■ पृष्ठ 12 ■ मूल्य ₹. 3.00

## 126 करोड़ में जलेगा भोपाल का 'जहर'

5,000 से अधिक लोगों  
की गई थी जान

भोपाल।

40 साल बाद भोपाल में पड़े जहर के जलाया जाएगा। इसके साथ ही भोपाल गैस त्रासदी की जान चली गई थी। यह जहरीले अवशेष उत्तरी भाग में आएगा। इसे इंटरो के पास पीथमपुर की रामकी कंपनी में जलाया जाएगा। इस काम के लिए 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह काम गैस त्रासदी रात एवं पुनरायोगिता की देखरेख में होगा। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम हादसे का है, जो गैस त्रासदी के बाद कालीन रुपरिपायन कार्बोइड की फैक्ट्री में है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद काम बेहद सावधानी से कराना होगा ताकि रास्ते में

साल बाद जलाया जाएगा। इसके लिए 126 करोड़ रुपये की राशि टेंडर लेने वाली कंपनी को दी गई है। हालांकि यह काम के से रुपरिपायन की जान नहीं हुई है। अब डर है कि जब इस जहर को नष्ट किया जाएगा, तब क्या इंटरो भी इसकी जरूर में आएगा। इसे इंटरो के पास पीथमपुर की रामकी कंपनी में जलाया जाएगा। इस काम के लिए 126 करोड़ रुपये खर्च होंगे और यह काम गैस त्रासदी रात एवं पुनरायोगिता की देखरेख में होगा। इस जहरीले कचरे को नष्ट करने का काम हादसे का है, जो गैस त्रासदी के बाद कालीन रुपरिपायन कार्बोइड की फैक्ट्री में है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद काम बेहद सावधानी से कराना होगा ताकि रास्ते में



### 126 करोड़ में जलेगा 'जहर'

कोई हादसा न हो। फिलहाल, विभाग और रामकी कंपनी के अधिकारी इस काम को कैसे अंजाम देना है, इस पर चर्चा कर रहे हैं।

अब केंद्र सरकार ने पैसे दे दिए हैं और जल्द ही इस काम को शुरू किया जाएगा।

### कंपनी पर उठ रहे सवाल

हालांकि, कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं को इस प्रक्रिया पर आपत्ति है। उनका कहना है कि रामकी कंपनी के पास इतनी बड़ी मात्रा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस कचरे के कुछ हिस्से को रामकी कंपनी में ही जलाकर देखा गया था। यह प्रयोग सफल रहा था और उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई थी। उसके बाद तय हुआ कि बाकी कचरे को भी यहीं नष्ट किया जाएगा, लेकिन राशि केंद्र सरकार देगी।

राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने बदले दो हॉल के नाम

नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन के अंशोक हॉल और दरबार हॉल का नाम बदल दिया गया है। राष्ट्रपति द्वौपदी मुर्मू ने ये फैसला लिया है।

राष्ट्रपति भवन के दो महत्वपूर्ण हॉल दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्रमशः गैलत्रं मंडप और अशोक मंडप कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी विज्ञप्ति में इस बात की जाकारी दी गई है। दरबार हॉल में कई अहम कार्यक्रम आयोजित होते थे। यहाँ गैलत्रं अवधार्ड दिए जाते थे। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दरबार हॉल का इस्तेमाल कोर्ट और विधानसभाओं के लिए भारतीय शासक और ब्रिटिश करते थे।

**केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ी**

नई दिल्ली। दिल्ली शरबनीति से जुड़े भ्रात्याचार मामले में राज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाइ जेल से विडियो कॉर्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। इसी के मौन लॉड्डिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। दिल्ली सरकार, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक बहुमत के फैसले से असहमति जारी है।

**ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद 4 महिलाओं की मौत**

दमोह। दमोह सरकारी और अपरेशन से जुड़े आतंकीय हमले में 4 महिलाओं को बच्चों के पहली दिलीवरी थी, जो ऑपरेशन से हुई। परिवार वालों को कहना है कि अप्यताप प्रबंधन की लापरवाही ने दुर्भुत्तु बच्चों से मां का आंचल छीन लिया।

**बांगलादेश से 6,700 भारतीय छात्र लौटे**

दाका। बांगलादेश में हिस्क झड़पों के बीच लगभग 6,700 भारतीय छात्र वहाँ से वापस लौट आए हैं। बांगलादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच घाटक झड़पें हो रही हैं। वे शेख हसीना की सरकार से सरकारी नौकरी में कोटा सिस्टम समाप्त करने की मांग रहे हैं। कुछ समाह पहले शुरू हुए झड़पों में अब तक 180 से ज्यादा लोग मरे जा चुके हैं।

**सुदर्शन ब्रिज पर हुए गड्ढे**

राजकोट। द्वारका का सिनेचर ब्रिज (सुदर्शन ब्रिज) पांच महीने में ही अपनी खबरसूती खो चुका है। कई जगहों से सीमें उड़ाई गई है, जीवंत लोगों द्वारा दिखाई देने लगी हैं। कुछ जगहों पर तो साड़ी की दीवारों से प्लास्टर उड़ाई चुका है। पीपल मोटी के इस डीम प्रोजेक्ट की तर्फ से सामने आने के बाद कलेक्टर से लेकर इंटरो की छात्रों की गंभीर खबर आयी है। इसके कारण पुरी जगहों से जीवंत लोगों द्वारा दिखाई देने की जगह बदल जाएगी। इसके कारण पुरी जगहों से जीवंत लोगों द्वारा दिखाई देने की जगह बदल जाएगी।

**सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केंद्र को बड़ा झटका**

## टैक्स नहीं है खनिजों पर ली जाने वाली रॉयल्टी

**9 जजों की संविधान पीठ ने बदल दिया 7 न्यायाधीशों की पीठ का फैसला**

नई दिल्ली।



1989 के फैसले को पलटा

सुप्रीम कोर्ट खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत एक महत्वपूर्ण मुद्रे पर सुनवाई कर रहा था। सामान्य यह था कि व्यवस्था खनिजों पर देय संघटनी एक टैक्स है और व्यवस्था सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही है तरह का टैक्स लगाने का अधिकार है या राज्य सरकार भी अपने क्षेत्र में खनिज भूमि पर लेवी लगा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सात जजों की संविधान पीठ का 1989 का फैसला गलत था, जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक टैक्स है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान की प्रतिविधि 50 के तहत संसद को खनिज अधिकारों पर लगाने का अधिकार नहीं है।

इन राज्यों को मिलेगी राहत

सीजेर्स चंद्रचूड़ द्वारा लिखित फैसले पर जस्टिस ह्विकेश सैयद, एस ओका, जेपी पारदीवाला, मोजे मिश्रा, ऊजवल भुयान, एसी शर्मा और एजी मधीया द्वारा संहारित व्यक्ति की गई। इस फैसले में कहा गया है कि निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी का नहीं है। इस फैसले से ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज संघर्षों को फायदा होगा। अब नौ-जजों की पीठ अगले बुधवार को फिर से विचार करेगी कि उनका फैसला पूर्वव्यापी होगा या नहीं। अगर यह फैसला पूर्वव्यापी लागू होता है तो केंद्र सरकार को तरफ से राज्यों के लिए भारी कराया देना पड़ सकता है। राज्य चाहते हैं कि यह फैसला पूर्वव्यापी रूप से लागू हो, जबकि केंद्र सरकार इसे भविष्य के लिए लागू करायी है।

क्या था 1989 का फैसला

साल 1989 में सात जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास संघ सूची (सूची-1) की प्रविधि 54 के तहत एसएमडीआरए जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार खानों और खनिज विकास के नियमन पर प्राथमिक अधिकार है। राज्यों के पास केवल एसएमडीआरए के तहत रॉयल्टी एक्ट करने का अधिकार है और वे खनन और खनिज विकास पर कोई और कर नहीं लगा सकते। कोई ने यह भी कहा था, हमारा मानना है कि रॉयल्टी एक्ट करने के लिए रॉयल्टी पर उपकर, रॉयल्टी पर एक कर है, राज्य विधानसंघल की क्षमता से पेरे हैं क्योंकि केंद्रीय अधिनियम की धारा 9 क्षेत्रों को करव करती है।

**6 महीने में पीतल हो गया गर्भगृह का सोना**

वाराणसी। ज्योतिर्पंथ मठ के शंकरनाथ अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया। दिल्ली में उन्होंने कहा- कर्मिण विश्वनाथ समेत देश के और कई मंदिरों से भी सोना धोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ समेत देश के और कई मंदिरों से भी सोना धोटाला हुआ है। काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में केसा सोना है, जो 6 महीने से पीला हो गया। भगवान के साथ आप हूल हुआ है, तो सामने आना चाहिए।

10 दिन पहले अविमुक्तेश्वरानंद ने केवलनाथ से 228 किलो सोना लागू कर रहे हैं। उन्होंने कोई चमक कम नहीं हो रही है। लेकिन, उन्होंने कोई चमक की मात्रा बढ़ा दी है। लेकिन, हमें ही आरोपी बनाकर बदाना करने की कोशिश की जा रही है। आरोपी को बदाना ही पड़ेगा। बात तो सिर्फ केवलनाथ की नहीं, बात तो विश्वनाथ मंदिर की भी है। उनके गर्भगृह में भी सोना



















# सरकार का सहयोग और जनता का साथ औद्योगिक विकास का है आधार: डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र को किया संबोधित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्यप्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा। यह कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए सेतु का काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कोयम्बटूर में इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट समिट का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापार और व्यवसाय के अधार पर विविध प्रदेश परस्पर नजदीक आएं और हम लिंक प्रधामंत्री नंदेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दिखाने में संकल्पित होकर कार्रवाएं करें। यहाँ के उद्योगपतियों ने कोयम्बटूर और त्रिपुरा को अपने बलबुते पर इंडस्ट्रियल हब के रूप में स्थापित किया है, अब मध्यप्रदेश आपको बुला रहा है, हम आपको व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के नए अवसर देंगे और प्रेम बांटें हुए मध्यप्रदेश एवं तमिलनाडु के संबंधों को अधिक मजबूत करने के दृष्टिकोण से यहाँ आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दक्षिण भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों कोयम्बटूर में आयोजित इन्वेस्ट एमपी-इंटरेक्टिव सत्र का दीप प्रज्ञालित कर तथा तुलसी के पौधे में जल अपवाह का शुभारंभ किया। कोयम्बटूर टैक्सिटाइल एवं गार्मेंट, इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे औद्योगिक सेक्टर के लिए जाना जाता है। प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों के प्रोत्साहन के लिए भोपाल में होने वाली लोबल इन्वेस्ट समिट में तमिलनाडु के उद्योगपतियों को समर्पित करने के उद्देश्य से कोयम्बटूर में रोड शो और निवेशकों व उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्टिव सत्र आयोजित किया गया। सत्र में 1200 से अधिक प्रतिविधियों ने भागीदारी की तथा मध्यप्रदेश में निवेश के लिए 3500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए।



वर्ष 2025 उद्योग वर्ष के रूप मनाया जाएगा

करने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

**राज्य का इको-सिस्टम अत्यंत अनुकूल**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में भी टैक्सिटाइल एवं गार्मेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल एवं इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्यप्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। उद्योगपतियों के लिए मध्यप्रदेश में निवेश कर आपने व्यापार-व्यवसाय बढ़ावा दिया है। मध्यप्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को अकार्पित करने के लिए प्रदेश में लागू विशेष रेडीमेड गारमेंट पोलिसी में स्थाई पूँजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए जबलपुर शहर में अति आधिकारिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है।

**निवेश क्रांति का हिस्सा बनें  
तगिनाइ के उद्योगपति**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा, में आपको प्रदेश में चल रही निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का निमित्त देने आया है। युवा विश्वास है कि मध्यप्रदेश में उपलब्ध अवसरों का उपर्युक्त उद्योगपतियों के लिए आपार संभावनाओं के साथ सरकार का सहयोग एवं जनता का साथ है।

**जनीनीटी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट**

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री के 10 से अधिक ऑफिस एमपी तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निमातों की उपस्थिति मध्यप्रदेश में है। कमर्शियल व्हीकल्स निमांग के लिए अमरीका और इंडिया एवं जनता का साथ है।

**जनीटी टेट्वाल ने संत शिरोगणि रविदास ग्लोबल टिक्ल पार्क का किया औंचक निरीक्षण**



भोपाल। कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री गोतम टेट्वाल ने संत शिरोगणि रविदास ग्लोबल टिक्ल पार्क (जॉइस्पैस) का औंचक निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करे विद्यार्थियों से रू-बूरु चर्चा की शिक्षित ठीक है। संजय पांडे यूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनके एक नजदीकी रिसेटरार खेड़वा में निरीक्षक हैं।

तथा एनसीलीसी की भी कई बड़ी छोटी इकाइयां कार्रवाई हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर के लिए आवश्यक सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर, द सेंटल फार्म मीनीनीट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बुदनी में और पीथमपुर में ऑटो कलस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक निवाया भी उपलब्ध है।

**उद्योग स्थापना के लिए मध्यप्रदेश है पीपुल्स फ्रेंडली**

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य को खनिज-बन-जल और पर्यावरण सम्पदा का भरपूर उपहार मिला है। उद्योगों की स्थापना और निवेश के लिए मध्यप्रदेश पीपुल्स फ्रेंडली और एनवाइनमेंट फ्रेंडली और एनवाइनमेंट फ्रेंडली डेव्हेनेशन है। प्रदेश की अन्य राज्यों से कोटिकटिवी अच्छी है, प्रदेश के इंडस्ट्रियल कोरिडोर्स से विभिन्न एक्सप्रेस-वे गुजर रहे हैं। प्रदेश विद्युत संस्करण स्टेट है, उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक की भी उपलब्धता है।

**तीन एनओयू पर हुए हस्ताक्षर**

इंटरेक्टिव सत्र में 25 से अधिक उद्योगपतियों तथा 4 प्रमुख उद्योग संस्टानों के साथ बन-टू-बन बैठक की गई साथ ही राज्य के एक लिल-एक उत्पादन तक पहुंचना का यह सबसे उपयुक्त समय है। मध्यप्रदेश में निवेश के लिए जबलपुर शहर में अति आधिकारिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की जा रही है। और स्किल एवं कलस्टर डेवलपमेंट में सहायता के लिए तरुण गारमेंट पोलिसी में स्थाई पूँजी निवेश के 200 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए जबलपुर शहर में अति आधिकारिक स्किल डेवलपमेंट कॉर्टन के उत्पादन और रक्केबों को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज शेयरिंग और अधिकारिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की उपलब्धता है। और यहाँ व्हीनी ग्रीन ग्रीन एवं जर्मन टैक्सिटाइल कोर्टन के लिए आपार संभावनाओं को आधारित करने की वित्तीय सहायता का लागू हुए हैं।

**तीन एनओयू पर हुए हस्ताक्षर**

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मध्यप्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शेयरिंग के लिए साउथ इंडिया मिल्स एक्सोसिएशन के साथ भी एमओयू किया गया।

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। आपार संभावनाओं के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। आपार संभावनाओं के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। आपार संभावनाओं के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मध्यप्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शेयरिंग के लिए साउथ इंडिया मिल्स एक्सोसिएशन के साथ भी एमओयू किया गया।

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। आपार संभावनाओं के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। आपार संभावनाओं के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया।

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। मध्यप्रदेश में कपास की खेती को बढ़ावा देने और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट शेयरिंग के लिए साउथ इंडिया मिल्स एक्सोसिएशन के साथ भी एमओयू किया गया।

उपर्योगिता के बारे में विस्तृत चर्चा की। मंत्री श्री टेट्वाल ने जीप्सीपी के हास्टल में उपलब्ध कराई जा रही हुई सुविधाओं की जानकारी ली। विद्यार्थियों ने निवेश के लिए टैक्सिटाइल इंडस्ट्री की संबंधी एमओयू पर हस्त

